साप्ताहिक
जागत गांव हमार
पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक
RNI-MPHIN/2015/72544
चौपाल से भोपाल तक
भोपाल, सोमवार 21-27 मार्च 2022, वर्ष-7, अंक-51
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

बड़ी समस्या: शिकार की अनुमति पर नहीं हो पाया फैसला

किसानों की फसल निगल रहीं नीलगाय

नीलगाय को लेकर नौ माह से सरकार के पास प्रस्ताव लंबित

भोपाल। संवाददाता

ओलावृष्टि, अतिवृष्टि आदि समस्याओं से जूझ रहे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए नीलगाय भी बड़ी समस्या बने हुए हैं। रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास, छतरपुर, सागर, रीवा, शहडोल सहित प्रदेश के 36 जिलों में नीलगाय की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके सही आंकड़े वन विभाग के पास भी नहीं हैं, पर विभाग यह स्वीकारता है कि इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। ऐसे में विधायकों ने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया। विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय द्वारा विधानसभा में लगाए प्रश्न पर वनमंत्री विजय शाह ने लिखित जवाब में कहा कि राजस्व क्षेत्र में नीलगाय की जानकारी ग्रामीणों की सूचना पर आधारित होती है। उधर, सरकार पिछले एक साल में नीलगाय के शिकार के नियमों को सरल नहीं कर पाई है। इसका प्रस्ताव सरकार स्तर पर लंबित है। सूअर, हिरन की तरह नीलगाय भी खड़ी फसलों को बर्बाद करती हैं। यह दूसरे वन्यप्राणियों की तुलना में ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इससे परेशान किसान कई साल से सरकार से गुहार लगा रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र में भी यह मामला उठा है।

सरकार दे रही मुआवजा

वनमंत्री विजय शाह ने लिखित जवाब में कहा है कि नीलगाय से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार करती है। किसानों को मुआवजा दिया जाता है। हालांकि सरकार के पास इस समस्या का स्थाई हल अब भी नहीं है। सरकार 10 साल से नीलगाय की संख्या नियंत्रित करने पर काम कर रही है। पहले नसबंदी पर काम किया गया, जो असफल रहा। इसके बाद नीलगाय के शिकार के नियम सरल करने पर मंथन हुआ।

विधायक दे चुके सुझाव

वन विभाग ने करीब डेड़ साल में संशोधन का प्रारूप तैयार किया, जिसमें नीलगाय के शिकार की अनुमति के अधिकार अनुविभागीय राजस्व अधिकारी से छीनकर एसडीओ वन को दिया जाना प्रस्तावित है। प्रारूप जुलाई 2021 में सरकार को भेजा गया है। विधायकों से भी सुझाव मांगे गए हैं, पर निर्णय नहीं हो पा रहा है।

20 साल पुरान नियम बदलेगा

अगर सरकार ने प्रदेश में नीलगाय और जंगली सूअर के शिकार की अनुमति दे दी तो किसानों को आवेदन करने के 8 दिन में मिल जाएगी। हालांकि लाइसेंसी हथियार रखने वालों को ही अनुमति मिलेगी। वन विभाग का 20 साल पुराना नियम बदला जाएगा।

इन क्षेत्रों में नील गाय का आतंक

प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, पन्ना, छतरपुर, रीवा सर्किल से जुड़े क्षेत्र में नीलगाय और खंडवा, होशंगाबाद, इटारसी, मंडला, उमरिया, डिंडोरी व टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्र में जंगली सूअर आ सबसे ज्यादा आतंक है। यहां के किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं।

एसडीओ फॉरेस्ट के पास से मंजूरी मिलने लगेगी तो नीलगाय या जंगली सूअर से प्रभावित लोग आवेदन करेंगे। वैसे इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि सीमित संख्या में अनुमति दी जाए। यह सही है कि इन दोनों जानवरों की संख्या ज्यादा होने की वजह से यह फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं।

-आलोक कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मप्र

सभी जिला सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश

बैंक किसानों की इच्छा के बगैर फसल बीमा की राशि में नहीं कर पाएंगे कटौती

- » फसल बीमा दावे की राशि को केवल उनकी मर्जी से ही काटा जाएगा
- » फसल के कालातीत ऋण-शेष मध्यावधि ऋण कटौती किया जाएगा
- » किसी भी चालू ऋण की कटौती बीमा दावे से अब नहीं की जाएगी
- » खाते में जमा राशि पर भी बिना किसी कारण होल्ड नहीं लगेगा

भोपाल। फसल बीमा की राशि को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस संबंध में सरकार ने सहकारी बैंकों को दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके तहत अब बैंक किसानों की इच्छा के बगैर फसल बीमा की राशि से कर्ज की कटौती नहीं कर पाएंगे। वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश देते हुए राज्य शासन ने कहा फसल बीमा दावे की राशि से केवल फसल के कालातीत कर्ज-शेष मध्यावधि परिवर्तन ऋण कटौती किया जाएगा। हवीं जहां एक ओर सरकार द्वारा ये नियम लागू किए गए हैं। वहीं किसानों का कहना है कि बैंक द्वारा चालू वर्ष के दिनों में किसान बीमा राशि से कटौती की जा रही है। इस

होल्ड होगा समाप्त

यदि किसान अपनी सहमति से वार्षिक ऋण या अन्य कटौती कराना चाहते हैं तो बैंक किसानों की सहमति के अनुसार ही कटौती कर सकेंगे। बैंक ने किसानों के बीमा दावे की राशि में से अधिक कटौती की तो उसे वापस खाते में भेजा जाए। किसानों के खाते में निकासी पर किसी भी तरह का होल्ड ना लगाया जाए और लगे हुए होल्ड को तत्काल समाप्त किया जाए।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि अब अगर किसान ने बैंक से कर्ज भी लिया है तो यह राशि उसके खाते मे पहुंचेगी और उसे यह राशि दी जाएगी। अब बैंक किसान के खाते को न होल्ड कर पाएंगे और न ही एटीएम ब्लॉक कर सकेंगे। बैंकों ने प्रदेश में किसानों को यह राशि देना शुरू कर दी है।

कमल पटेल, कृषि मंत्री

खंडवा के किसान जीत, डूब में आई थी 21 एकड़ जमीन

सरकारी संपत्ति कुर्क कर किसान को मिलेगा 16 करोड़ मुआवजा

-रिकवरी नहीं मिलने पर पहुंचा था कोर्ट, अब मिला न्याय

खंडवा। संवाददाता

मध्यप्रदेश के किसान ने 22 साल तक चली जमीन की कानूनी जंग जीत ली। जिसके बाद अब उसे सरकारी संपत्ति कुर्क कर 16 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मामला हरसूद का है। इंदिरा सागर डैम के डूब क्षेत्र में उसकी 21 एकड़ जमीन आ गई थी। मुआवजा पाने के लिए उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसके बाद कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए, आज की गाइडलाइन के हिसाब से उसे रिकवरी देने का फैसला दिया। रिकवरी नहीं मिलने पर वह एक बार फिर कोर्ट पहुंचा। अब जबलपुर हाईकोर्ट ने कलेक्ट्रेट और नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिकल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की संपत्ति कुर्क करते हुए किसान को मुआवजा देने को कहा है।

21 एकड़ जमीन

सरकार को 21 एकड़ जमीन पर 3 लाख के मुआवजे के बदले 16 करोड़ देना है। यह रिकवरी कलेक्ट्रेट और एनएचडीसी के जनरल मैनेजर, कार्यपालन यंत्री व भूअर्जन अधिकारी के जरिए कराई जानी थी। उन्होंने अपने वकील मयंक मिश्रा के जरिए हाईकोर्ट में अपील की थी।

कुर्की को लेकर टीम दफ्तर आई थी। केस में पार्टी बनाया है, लेकिन भुगतान एनएचडीसी को ही करना होगा। इसको लेकर एनएचडीसी के अधिकारियों से चर्चा हो गई है।

अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर, खंडवा

पांच लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा केंद्र, केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने लोकसभा में दी जानकारी

किसानों को खेती के लिए ड्रोन खरीदने सरकार ने खोला खजाना

भोपाल। संवाददाता

देश में खेती-किसानी को किसानों के लिए सरल और सुलभ बनाने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। जिसके तहत खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को केंद्र सरकार बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में सरकार खेती के लिए ड्रोन की खरीददारी करने वालों को भी मदद उपलब्धक करा रही है। जिसके तहत केंद्र सरकार खेती के लिए ड्रोन की खरीददारी पर अधिकतम 5 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्धर करा रही है। यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीते दिनों लोकसभा में दी है। तोमर के अनुसार किसान सहकारी समिति के अधीन काम कर रहे नए और पुराने कस्टम हायरिंग सेंटर, किसान उत्पादक संगठन और ग्रामीण उद्यमी, अगर खेती के लिए ड्रोन की खरीददारी करते हैं, तो उन्हें ड्रोन खरीद के लिए ड्रोन और उसकी मूल लागत का 40 फीसदी या 4 लाख रुपए (जो भी कम हो) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वहीं स्थापित किए गए कस्टम हायरिंग सेंटर को ड्रोन की मूल लागत का 50 फीसदी या 5 लाख अधिकतम (जो भी कम हो) की वित्तीय सहायता उपलब्धर कराई जाती है।

ड्रोन के लिए एसओपी हो चुकी जारी

खेती- किसानी में ड्रोन टेक्नोलॉजी के अनूठे लाभों को देखते हुए कृषि और किसान कल्याण विभाग ने दिसंबर 2021 में पाबेश्कि डोमेन में कीटनाशक और पोषक तत्वों के छिड़काव में ड्रोन के उपयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की थी। तोमर के अनुसार यह एसओपी ड्रोन के सुरक्षियत संचालन के लिए प्रभावी और संक्षिप्त निर्देश प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत में ड्रोन के उपयोग और संचालन को विनियमित करने के लिए ड्रोन नियम 2021 प्रकाशित किया है, जिसका सभी ड्रोन संचालन के लिए पालन किया जाना है और इन नियमों के अनुसार ड्रोन संचालन के लिए विशिष्ट पहचान संख्या आवश्यक है। हालांकि, मानव रहित विमान ऑपरेटर परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

2.25 करोड़ किए जा चुके जारी | केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि ड्रोन तकनीक को किसानों और इससे जुड़े संगठनों के लिए सस्ती बनाने के उद्देश्य से सरकार कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन के तहत कृषि विज्ञान केंद्र, राज्यों कृषि विवि और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान को भी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। वहीं उन्होंने बताया कि ड्रोन की खरीद पर वित्तीय मदद देने की योजना के तहत चालू वर्ष के दौरान अब तक 2.25 करोड़ जारी किए जा चुके हैं।

पहली बार 50 समर्थन मूल्य केंद्रों पर होगी खरीदी

नर्मदांचल में चने से चमकेगी अन्नदाताओं की किस्मत

नर्मदापुरम। संवाददाता

जिले की उर्वरा माटी ने मुख्य खाद्यान्न गेहूं की पैदावार में प्रदेश के सभी जिलों में प्रथम स्थान बना चुका है। बीते वर्ष पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर गेहूं की पैदावार में प्रदेश में जिला रिकॉर्ड बना चुका है। अब इस बार मौसम ने साथ दिया है। इस कारण चना की पैदावार में भी नर्मदापुरम जिला प्रदेश के अन्य जिलों में रिकॉर्ड बनाने की स्थिति में पहुंच गया है। इस बार जिले के किसानों ने पूर्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 63 हजार हेक्टेयर में चना की बोवनी की है। इस बार मौसम भी चने की फसल के अनुकूल रहा है। इस कारण किसानों की किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि इस बार भी समर्थन मूल्य से अधिक में व्यापारी चने की खरीदी करने के मूंड में है। 25 मार्च से चना की खरीदी भी संभावित है।

अच्छी स्थिति में चना

पूरे जिले में चना की फसल ठीक है। चना की बोवनी करने वाले किसान सुदीप पटेल, सुरेंद्र गौर,केशव गौर का कहना है कि चना अच्छी हालत में है। इस बार रोग भी नहीं लगा है। मौसम भी ज्यादा खराब नहीं हुआ है। जिससे चना की फसल में खराबी नहीं आई है।

50 केंद्र बनाने की तैयारी

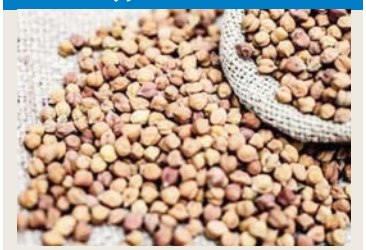

पूर्व 11 ही केंद्रों पर चने की समर्थन मूल्य पर खरीदी होती थीं इस चने का रकबा बढ़ने के कारण प्रशासन के द्वारा जिले की मंडियों सहित सोसायटियों में भी केंद्र बनाए जा रहे हैं। कुल 50 केंद्र बनाए जा रहे हैं। बीते वर्ष 5125 रुपए प्रति क्विंटल के भाव समर्थन मूल्य था जो इस बार और बढ़ाया जाएगा।

20 हजार किसानों ने कराया पंजीयन

इस बार जिले के 19,950 किसानों ने समर्थन मूल्य पर चना बेचने के लिए पंजीयन कराया है। जो अब तक का सबसे अधिक है। चने की पैदावार भी इस बार पिछले वर्ष से अधिक हो रही है। इसलिए किसानों को अच्छी आय होना है।

अब हो रहा 18 से 20 क्विंटल

कृषि विभाग के अधिकारियों के अलावा किसानों ने बताया कि पहले चने का रकबा कम होता था। पैदावार भी कम होती थी। इस बार मूंग की बोवनी को ध्यान में रखते हुए चने के रकबा बढ़ाने पर जोर दिया गया था। किसानों ने चना बोने में रुचि भी दिखाई इससे यह फायदा हुआ कि इस बार चने की पैदावार बीते वर्षों की तुलना में दो गुने से भी अधिक होने का अनुमान है। किसान नरेंद्र पटेल ने बताया कि इस बार चना की पैदावार प्रति हेक्टेयर 18 से लेकर 21-22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक निकल रहा है। जो अब तक रिकॉर्ड उत्पादन है।

100 करोड़ का बिक सकता है चना

जिले में जिस प्रकार पैदावार हुई है उससे तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि 63 हजार से अधिक हेक्टेयर में बोए गए चने की पैदावार से जो राशि किसानों के पास पहुंचेगी वह 100 करोड़ के लगभग रहेगी। क्योंकि समर्थन मूल्य से अधिक में व्यापारी चना खरीदने की तैयारी में है।

इस बार चने की फसल के लिए मौसम बिल्कुल ठीक था। रकबा भी पहली बार इतना बढ़ा था। अभी जो किसानों से फीडबैक मिल रहा है उससे प्रति हेक्टेयर 20से लेकर 22 क्विंटल तक निकल रहा है। इससे यह माना जा रहा है कि अब तक पैदावार का रिकॉर्ड बनना है।
जेआर हेडाउ, उप संचालक कृषि, होशंगाबाद

अब बड़ा कदम उठाने जा रही शिवराज सरकार

खेती के जरिए कैंसर पर लगाम लगाने की तैयारी

भोपाल। संवाददाता

वैश्विक तौर पर जानलेवा बीमारी माने जाने वाले कैंसर की रोकथाम को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार काफी सजग है। साथ ही, इस पर लगाम लगाने को लेकर एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। सरकार का दावा है कि, आगामी जिनों में वो एक लाख हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती कराने की तैयारी कर रही है, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से निजात दिलाने में कारगर साबित होगी। हालांकि, सरकार द्वारा निर्धारित एक लाख हेक्टेयर में जैविक खेती का लक्ष्य पहले चरण का है। सरकार द्वारा धीरे-धीरे जैविक खेती का रकबा लगातार बढ़ाया जाएगा। शोधकर्ताओं ने लंबी रिसर्च के बाद पाय है कि, खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशक के इस्तेमाल से कैंसर समेत अन्य कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। इसी रिसर्च को आधार मानते हुए प्रदेश सरकार अब जैविक खेती को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में शिवराज सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि, पहले चरण में 1 लाख हेक्टेयर जमीन पर जैविक खेती की तैयारी शुरू कर दी गई है। खासतौर पर सबसे अधिक खेती नर्मदा किनारे बसे गांवों की जमीनों पर किया जाएगा। कृषि मंत्री ने बताया कि, रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का अर्ग फसलों पर भी कहीं न कहीं दिखता है, जिसकी वजह से न सिर्फ गंभीर बीमारियां जन्म ले रही हैं, बल्कि लगातार बेलगाम भी होती जा रही हैं। मानव जीवन पर लगातार बढ़ रहे खतरे को कम करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इसी के तहत किसानों को जैविक खेती की तरफ प्रेरित करने का काम शुरू हो गया है। कृषि विभाग युद्ध स्तर पर इस कार्य में जुट गया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि, जैविक खेती करने वालों को बड़ा लाभ देने की तैयारी की गई है। जैविक खेती के लिए तैयार हुई फसलों के दाम भी अधिक रहेंगे, क्योंकि इसकी डिमांड रासायनिक खेती के मुकाबले कई ज्यादा है।

मिर्च की खेती से किसानों को होगा अच्छा मुनाफा

मध्य प्रदेश और कर्नाटक मिर्च उत्पादक राज्य

भोपाल। संवाददाता

देश भर में मसालों की खेती पर खासा फोकस दिया जा रहा है। मिर्ची की खेती भी उनमें से एक है। हरी मिर्च खाने के भी फायदे होते हैं। यह विटामीट से भरपूर होती है। मिर्च में पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन भरपूर मात्रा में होती है। मिर्च का उपयोग लंबे समय से दर्द से राहत के लिए किया जाता है मिर्च मिर्च के अर्क का उपयोग गठिया, सिरदर्द, जलन और नसों के दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। यह भी दावा किया जाता है कि उनके पास प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और कोलेस्ट्रॉल कम करने की शक्ति है। नेशनल चिली टास्कफोर्स के अनुसार मिर्च देश में मसालों के कुल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 6,500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष) है। जबकि मसालों का कुल निर्यात लगभग 21,500 करोड़ का है। भारत से कुल मसालों का निर्यात पिछले साल 27,193 करोड़ से अधिक हुआ है। इसमें मिर्च का निर्यात भी शामिल है। इसका फायदा मिर्च की खेती करने वाले किसानों को होगा। यही कारण है कि किसान मिर्च की खेती करने के लिए अब आगे आ रहे हैं। मिर्च की अधिक पैदावार करने और किसानों को मिर्च की खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए प्रसंस्कृत मिर्च के निर्यात को बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं, जो कुल निर्यात का केवल 30 प्रतिशत है, जबकि शेष साबुत सूखी मिर्च है।

कर्नाटक के ब्यादगी मिर्च की काफी मांग

कर्नाटक में उगाई जाने वाली ब्यादगी मिर्च की रंग और तीखेपन के कारण विश्व बाजार में काफी मांग है। पूसा ज्वाला, सोना-21, जवाहर, सदाबहार, अग्नि, गुंटूर, प्रकाशम, कृष्णा क्षेत्र में उगाई जाने वाली तेजा और गुंटूर सन्नम किस्में आंध्र प्रदेश को भारत में मिर्च उत्पादन में अग्रणी बनाती हैं। कर्नाटक और मध्य प्रदेश अन्य प्रमुख मिर्च उत्पादक राज्य हैं। भारत से चीन की लाल मिर्च का आयात वित्त वर्ष 18 तक 10,000 टन से बढ़कर अगले वर्ष 75,000 टन और वित्त वर्ष 2020 में लगभग 1.4 लाख टन हो गया है, क्योंकि चीनी लोगों ने भारतीय मसाले को पसंद किया है, जो कि इससे कहीं ज्यादा गर्म है।

मिर्च उत्पादन में भारत आगे

भारत मिर्च उत्पादन और निर्यात में वैश्विक नेता बना हुआ है, और आंध्र प्रदेश वाणिज्यिक फसल पैदा करने वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर है। भारत में उगाई जाने वाली मिर्च की गुणवत्ता को दुनिया भर में सबसे अधिक पसंद किया गया था, और निर्यात ने पिछले 10 वर्षों में मात्रा और मूल्य दोनों के मामले में स्वस्थ वृद्धि दिखाई थी। कीटनाशक अवशेष और एफ्लाटॉक्सिन नगण्य मात्रा में पाए गए। आज तक, भारतीय मिर्च निर्यात वैश्विक मिर्च व्यापार में 50 फीसदी से अधिक का योगदान देता है, चीन इसका निकटतम प्रतियोगी है, लेकिन यह दूसरे स्थान पर बहुत पीछे है।

जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि में खेती को सस्ता बनाने किए जा रहा रिसर्च

खेती को आसान, सस्ता बनाने लैब में तैयार हो रहे शोध

जबलपुर। संवाददाता

मंथन सभागार में रिसर्च काउंसिल की मीटिंग विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. प्रदीप कुमार बिसेन ने कहा कि अनुसंधान व विज्ञान का चमत्कार ही है कि विभिन्न फसलों की 305 किस्मों को विवि द्वारा तैयार किया। वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखकर आगामी समय में किसानों के हित और जलवायु परिवर्तन, उन्नत किस्में, खेती की तकनीक, तकनीकी का व्यवसायिक लाभ पर भी काम जोर शोर से करना होगा। हम जीआई टैग, पेटेट और नवाचार के लिए कृषि के अनुसंधान की रणनीति पर काम कर रहे हैं। कृषि विवि के संचालक अनुसंधान सेवाएं डॉ. जीके कौतू द्वारा शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों पर पावर पाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी बात प्रस्तुत की। इस दौरान निदेशक खरपतवार अनुसंधान निदेशालय आईसीएआर जबलपुर डॉ. जेएस मिश्रा ने कहा कि अनुसंधानों का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे इसके लिए विशेष प्रचार-प्रसार की जरूरत है। एक विशेष रोड मैप तैयार कर इसे अमलीजामा पहनाना होगा। नरसिंहपुर जिले के प्रगतिशील किसान राकेश दुबे और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के कृषक केसलाल ने किसानों की कृषि क्षेत्र की अनेक व्यवहारिक समस्याओं से अवगत कराया। शोध के माध्यम से किस तरीके से कृषि विवि उन्नयन एवं कार्य कर सकता है। इस विषय पर अपनी बात भी रखी।

रिसर्च काउंसिल ने इन पर दिया जोर

- » ब्रीडिंग मटेरियल का पंजीयन विश्वविद्यालय के स्तर पर करना। नई किस्मों का विश्वविद्यालय स्तर पर बीज की उपलब्धता।
- » तकनीकी को मान्यता एवं प्रभाव आंकलन करना, शोध की तकनीक का व्यवसायिक कैसे करें, इस पर अध्ययन करना।
- » फार्म मशीनरी का विश्वविद्यालय स्तर पर म्यूजियम तैयार करना, विश्वविद्यालय के माध्यम से नवाचार का प्रचार प्रसार कैसे करें।
- » अनुसंधान से संबंधित परियोजनाओं में उपकरणों की खरीदारी में केंद्रीय कमेटी सिस्टम तैयार करना।
- » रिसर्च काउंसिल कमेटी में प्रगतिशील किसानों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

यह रहे मौजूद

विवि के संचालक विस्तार सेवाएं डॉ. दिनकर शर्मा, संचालक शिक्षण डॉ. अभिषेक शुक्ला, संचालक प्रक्षेत्र डॉ. दीप पहलवान, कृषि कॉलेज जबलपुर के अधिष्ठाता डॉ. शरद तिवारी, आईपीआरओ डॉ. शेखर सिंह बघेल एवं विवि के अंतर्गत संचालित समस्त कॉलेजों के अधिष्ठाता, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों के प्रमुख एवं विवि के समस्त विभागाध्यक्ष अनुसंधान के क्षेत्र से जुड़े कृषि वैज्ञानिक की महत्वपूर्ण उपस्थिति रही।

परिसर में लगेगी मिल्क एटीएम मशीन

नानाजी देशमुख विवि दिलाएगा शुद्ध दूध

जबलपुर। संवाददाता

नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय द्वारा अपने परिसर और वेटनरी महाविद्यालय में मिल्क वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। ये एटीएम मशीन की तरह काम करेगी। कोई भी शहरवासी कार्ड डालकर अपनी जरूरत के अनुसार दूध निकाल सकेंगे। लाइव स्टॉक प्रोडक्ट के इंचार्ज डॉ. पीके सिंह के मुताबिक विश्वविद्यालय व महाविद्यालय परिसर में मिल्क एटीएम जल्द लगाया जाएगा। टेंडर की प्रक्रिया जारी। मिल्क एटीएम से लोग अपनी जरूरत के अनुसार कम दामों में शुद्ध दूध प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय में एटीएम कार्ड की तरह कार्ड बनाया जाएगा। इसे आसानी से जरूरत के अनुसार रिचार्ज कराया जा सकेगा। मशीन में कार्ड स्वाइप करते ही जरूरत के अनुसार दूध मिल जाएगा।

विवि के नाम होंगे दूध के पैकेट

विवि में जल्द ही अमूल और सांची के पैकेट की तरह विवि अपने नाम से दूध पैकेट का निर्माण करेगा, जो बाजार में उपलब्ध होगा। विवि में मशीन लगाई गई है। वर्तमान में विवि में 550 लीटर दूध उत्पादित हो रहा है। इसमें 450 लीटर दूध का विक्रय और शेष दूध से खोवा, पनीर का निर्माण किया जा रहा है। प्रसंस्करण के इस कार्य से दूध से अधिक आय की जा सकती है। इसके लिए किसानों को विश्वविद्यालय द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

48 रुपए किलो दे रहे दूध

विवि में 48 रुपए की दर से शुद्ध दूध बेचने का कार्य अभी किया जा रहा है। इसके लिए कार्ड बनाया जाता है। और कूपन दिए जाते हैं। विवि के कर्मचारियों द्वारा दूध की सप्लाई की जाती है। इसमें कंटेनर पर सील लगाने का कार्य किया जाता है। जिससे दूध में मिलावट की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। जबकि बाजार में 60 रुपए प्रति लीटर दूसरे डेयरी संचालक दूध बेच रहे हैं।

पिपरिया में 3500 रु. क्विंटल बिकी पूसा बासमती धान

पिपरिया। कृषि उपज मंडी में पूसावन बासमती धान के भाव अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। मार्च माह में पूसा बासमती के दाम लगातार तेज होते जा रहे हैं। मंडी सचिव राघवेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि मंडी में बासमती पूसावन के भाव 3500 रुपए प्रति क्विंटल तक बोले गए। जो बीते वर्षों में अब तक अधिकम है। मंडी में सीजन में अब तक बासमती धान की आवक 13 लाख क्विंटल से अधिक दर्ज हो चुकी है। बीते दो माह से मंडी में बासमती धान के दाम 25 सौ से 26 सो रुपए तक चल रहे थे। भाव बढ़ने से मंडी में धान की आवक में कोई खास वृद्धि दर्ज नहीं कि गई। किसानों का कहना है कि अब तो बड़े किसानों का माल ही बचा है। अधिकांश माल तो व्यापारियों के पास स्टाक में है। जिससे धान के भाव बढ़ने से किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला। मंडी में पूसावन की लगभग 4 हजार क्विंटल की आवक दर्ज की गई।

सिवनी मालवा के किसान ने विश्व शांति का किया आह्वान

अनाज से बनाई रूस-यूक्रेन के राष्ट्रपति की तस्वीर

सिवनीमालवा। संवाददाता

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर लोग आशंकित हैं। इस युद्ध को रोकने के लिए सभी कोशिशें अब तक विफल साबित हुई है। दोनों को देशों से शांति कायम करने की अपील नर्मदापुरम जिले के डोलरिया विकासखंड के किसान योगेंद्र सिंह सोलंकी ने की है। किसान योगेंद्र ने रूस व यूक्रेन के राष्ट्रपति की अनाज से तस्वीर बनाई है और विश्व शांति की अपील की है। सोलंकी का कहना है कि रूस ने युद्ध में परणाणु बम के इस्तेमाल की धमकी दी है, ऐसे में नुकसान युक्रेन को तो होगा ही साथ ही पूरा विश्व इसके दुष्परिणाम झेलेगा। किसान सोलंकी का कहना है कि युद्ध में परमाणु बमों का इस्तेमाल कर अनाज के दुश्मन न बने। धरती का पूरा चक्र बिगड़ जाएगा।

कई नेताओं और भगवान की बनाई तस्वीरें- ग्राम सुपरली के किसान योगेंद्र सिंह सोलंकी ने अनाज से कई नेताओं और भगवान की तस्वीरें बनाकर घर मे एक प्रदर्शनी सी लगा रखी है। किसान ने अब तक अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, भजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सहित साई बाबा, गुरुनानक जी सहित कई महापुरुषों की तस्वीर भी बनाई है, जो आकर्षण का केंद्र है। वहीं किसान ने यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को लेकर दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की तस्वीर बनाकर संदेश दिया है।

घटनाओं को रोकने बनाऊंगा यंत्र

किसान योगेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि इन फोटो को बनाने का उद्देश्य यह भी है इन फोटो की प्रदर्शनी लगाकर बेचूंगा इससे जो पैसे मिलेंगे में उससे बोरवेल में गिरे बच्चों को निकालने वाला यंत्र बनाऊंगा और बच्चों की जान भी बचाऊंगा।

जीआई टैग मिलने के बाद बढ़ी उम्मीद

अब कृषि के क्षेत्र में चिन्नोर के चावल से चमका मध्य प्रदेश

रफी अहमद अंसारी। बालाघाट

मध्य प्रदेश के बजट में बालाघाट को कोई बड़ी सौगात नहीं मिली है। जबकि कृषि के क्षेत्र में चिन्नौर को जीआई टैग मिलने से सरकार ने दीगर फसलों को जीआई टैग दिलाने के साथ उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विशेष पहचान दिलाने पर जोर दिया है। कृषि के क्षेत्र में चिन्नौर को जीआई टैग मिलने से मध्य प्रदेश चमक उठा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खास पहचान देने के लिए सरकार और प्रशासन ने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। चिन्नौर को जीआई टैग मिलने से प्रदेश में अन्य फसलों को भी बल मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने शरबती गेहूं, पिपरिया की तुअर,काली मूंछ चावल और जीरा शंकर

को भी जीआई टैग दिलाकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विशेष पहचान दिलाने की बात पर जोर दिया है। कृषि वैज्ञानिक एवं सदस्य जीआई टैग बोर्ड डॉ. उत्तम बिसेन का कहना है कि चिन्नौर के बाद प्रदेश में अन्य फसलों को जीआई टैग दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सिहोर व सागर के शरबती गेहूं के साथ पिपरिया की तुअर, जीरा शंकर और काली मूंछ चावल को जीआई टैग दिलाने का प्रयास प्रक्रिया में है। बालाघाट की चानी चनौली को भी जीआई टैग दिलाने के लिए सरकार और प्रशासन ने कदम बढ़ाए हैं। चिन्नौर को जीआई टैग मिलने से कृषि के क्षेत्र में सरकार की रुचि बढ़ने दीगर फसलों को बल मिला है।

इनका कहना है

चिन्नौर को जीआई टैग मिलने से सरकार ने अन्य फसलों को भी प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। कृषि के क्षेत्र में चिन्नौर को जीआई टैग मिलने के बाद शरबती गेहूं, तुअर, काली मूंछ और जीरा शंकर जीआई टैग दिलाने पर जोर दिया है। चिन्नौर से अन्य फसलों को भी बल मिल रहा है।

डॉ. उत्तम बिसेन, कृषि वैज्ञानिक एवं सदस्य जीआइ टैग बोर्ड

जंगल की आग को लेकर संजीदा हो सरकार

रोहणी प्रसाद पांडेय
वरिष्ठ समाज सेवी

आज जंगलों को अंधाधुंध रूप से काटा जा रहा है। लिहाजा मिट्टी में गर्मी, ओजोन परत की कमी आदि में वृद्धि हुई है। हमारी विकास प्रक्रिया ने हजारों लोगों को पानी, जंगल और भूमि से विस्थापित कर दिया है। ऐसे में जंगल की रक्षा करना न केवल हमारा कर्तव्य होना चाहिए, बल्कि हमारा धर्म भी होना चाहिए। उत्तराखंड में पिछले 12 वर्षों में जंगल में आग लगने की 13 हजार से अधिक घटनाएं सामने आई हैं और इनमें हर साल औसतन 1978 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वन संपदा जलकर राख हो रही है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार जंगल की आग को बुझाने के लिए केवल समय से बारिश का होना ही एकमात्र कारगर विकल्प है।

जंगल में आग लगने की एक वजह मानव जनित भी है। कई बार ग्रामीण जंगल में जमीन पर गिरी पत्तियों या सूखी घास में आग लगा देते हैं, ताकि उसकी जगह नई घास उग सके। लेकिन आग इस प्रकार फैल जाती है कि वन संपदा को खासा नुकसान होता है। दूसरा कारण चीड़ की पत्तियों में आग का भड़कना भी है। चीड़ की पत्तियां (पिरुल) और छाल से निकलने वाला रसायन, रेजिन बेहद ज्वलनशील होता है। जरा-सी चिंगारी लगते ही आग भड़क जाती है और विकराल रूप ले लेती है। तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी मामूली बात लगती है, लेकिन जंगलों के सूखे पत्तों के लिए यह महत्वपूर्ण है। जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, पेड़ों और पत्तियों में से पानी की मात्रा कम होती जाएगी और ये ईंधन का काम करेंगे।

सूखी पत्तियों की रगड़ से आग का लगना और फैलना तेजी से होता है। भारतीय वन सर्वेक्षण ने वनाग्नि से हुई वार्षिक वन हानि 440 करोड़ रुपए आंकी है। जंगलों में लगी आग से कई जानवर बेघर हो जाते हैं और नए स्थान की तलाश में वे शहरों की ओर आते हैं। वनों की मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों में भी भारी कमी आती है और उन्हें वापस प्राप्त करने में भी लंबा समय लगता है। वनाग्नि के परिणाम स्वरूप मिट्टी की ऊपरी परत में रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होते हैं, जिस कारण भूजल स्तर भी प्रभावित होता है। इससे आदिवासियों और ग्रामीण गरीबों की आजीविका को भी नुकसान पहुंचता है। आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग तीन करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए वन उत्पादों के संग्रह पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। वनों में लगी आग को बुझाने के लिए काफी अधिक आर्थिक और मानवीय संसाधनों की जरूरत होती है, जिस कारण सरकार को काफी अधिक नुकसान का सामना करना पड़ता है।

वनाग्नि से वनों पर आधारित उद्योगों एवं रोजगार की हानि होती है और कई लोगों की आजीविका का साधन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। इसके अलावा वनों पर आधारित पर्यटन उद्योग को भी खासा नुकसान होता है। वनाग्नि से जलवायु भी प्रभावित होती है। इससे कार्बन डाई आक्साइड तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसों का काफी अधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है। इसके अलावा वनाग्नि से वे पेड़-पौधे भी नष्ट हो जाते हैं, जो वातावरण से कार्बन डाईआक्साइड को समाप्त करने का कार्य करते हैं। वर्तमान में अतिशय मानवीय अतिक्रमण ने वनों में लगने वाली आग की बारंबारता को बढ़ाया है। पशुओं को चराना, झूम खेती, बिजली के तारों का वनों से होकर गुजरना आदि ने इन घटनाओं में वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त, सरकारी स्तर पर वन संसाधन एवं वनाग्नि के प्रबंधन के लिए तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव इसका प्रमुख कारण है। अव्यावहारिक वन कानूनों ने वनोपज पर स्थानीय निवासियों के नैसर्गिक अधिकारों को खत्म कर दिया है, लिहाजा ग्रामीणों और वनों के बीच की दूरी बढ़ी है।

कुछ समय पूर्व खाद्य एवं कृषि संगठन के विशेषज्ञों के दल ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में भारत में जंगल की आग की स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि आर्थिक और पारिस्थितिकी के नजरिये से जंगल की आग पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, न ही क्षेत्रीय स्तर पर इस समस्या से निपटने के लिए कोई कार्ययोजना है। जंगल की आग पर आंकड़े बहुत सीमित हैं, साथ ही वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसके अलावा, आग की भविष्यवाणी करने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके खतरे के अनुमान, आग से बचाव और उसकी जानकारी के उपाय भी उपलब्ध नहीं हैं। इसमें कोई दो राय नहीं

है कि वनों में लगी आग से उन क्षेत्र विशेषों का भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश व्यापक स्तर पर प्रभावित होता है। अतः इन घटनाओं को न्यूनतम किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

आपदा प्रबंधन के समुचित उपायों के साथ-साथ आग के प्रति संवेदनशील वन क्षेत्र एवं मौसम में वनों में मानवीय क्रियाकलापों को बंद या न्यूनतम किया जाना चाहिए तथा संवेदनशील क्षेत्रों में आधुनिकतम तकनीकों से युक्त संसाधनों के साथ पर्याप्त आपदा प्रबंधन बल की तैनाती की जानी चाहिए। जंगल धू-धू कर जलते रहते हैं, वन संपदा खाक हो जाती है और वन विभाग सदैव की तरह मूकदर्शक बनकर असहाय बना बैठा रहता है। यदि वनों में आग लगने के बाद इंद्र देवता की कृपादृष्टि न हो तो न जाने कब तक जंगल धधकते रहें। ऐसे में राज्य सरकार को वास्तव में वनों की सुरक्षा को लेकर संजीदा होने तथा जमीनी वस्तुस्थिति को समझते हुए जंगलों की आग से निबटने के लिए सभी पहलुओं का गंभीरता से अध्ययन कर ठोस रणनीति बनानी होगी।

विलुप्त होने की कगार पर दस लाख प्रजातियां

भरत लाल पांडेय
पूर्व मंडल अध्यक्ष, भाजपा

जैव-विविधता पर जिनेवा में चल रहे सम्मेलन में 190 देशों के प्रतिनिधि, इसे होने वाले नुकसान को रोकने के वैश्विक उपायों को अंतिम रूप दे रहे हैं। सम्मेलन की बैठकों में जिस शब्द की अनुगूंज सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है, वह है- विलुप्त होने वाली प्रजातियां। जैव-विविधता को होने वाले नुकसान के लिए, आधिकारिक तौर पर 'विलुप्त या नष्ट होने' का इस्तेमाल किया जाता है। 14 मार्च से शुरू होकर 29 मार्च तक चलने वाले इस दो सप्ताह के सम्मेलन में जैव- विविधता को नष्ट होने से बचाने के लिए उपायों की अपरिहार्यता इसलिए जरूरी है, क्योंकि इसे जो नुकसान हुआ है, वह धरती के इतिहास में बिल्कुल अप्रत्याशित था। गौरतलब है कि सात सप्ताह के बाद ही जैविक विविधता पर चीन के कुन्मिंग में सम्मेलन होना है, जिसे कॉप-15 कहा जा रहा है।

कोरोना महामारी के चलते जैव-विविधता के नुकसान को रोकने के लिए महत्वपूर्ण वैश्विक रूपरेखा तैयार करने में पहले ही दो साल की देरी हो चुकी है। 2019 में, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर-सरकारी साइंस-पॉलिसी प्लेटफॉर्म (आईपीबीईएस) ने 'जैव-विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर पहली वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट' जारी की थी। इस रिपोर्ट के आकलन में कहा गया है कि जानवरों और पौधों की दस लाख प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं और इनमें से हजारों तो कुछ दशकों के भीतर ही विलुप्त हो जाएंगी।

मानोआ में हवाई विश्वविद्यालय में पैसिफिक बायोसाइंसेज रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर रॉबर्ट कोवी ने अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर जनवरी 2022 में अकशेरु की जीवों की स्थिति का व्यापक मूल्यांकन किया, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जानवरों की प्रजातियों का 95 फीसद हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर ज्ञात 20 लाख प्रजातियों में से साढ़े सात से तेरह फीसद यानी डेढ़ लाख से लेकर 2,60,000 प्रजातियां पहले ही गायब हो चुकी हैं। मतलब कि यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। सम्मेलन की कार्यकारी सचिव एलिजाबेथ मारुमा मरेमा ने सम्मेलन की बैठक का एजेंडा तय करते हुए कहा कि हमारा बस एक लक्ष्य है- जैव विविधता के होने वाले नुकसान की दिशा को मोड़ना और लंबे समय तक प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना। हालांकि समझौता-वार्ताओं के दूसरे दिन 15 मार्च को इस बात पर गहन चर्चा हुई कि क्या जैव-विविधता के नुकसान को बचाने के लिए 2020 के बाद की योजना में संख्यात्मक रूप से निर्धारित लक्ष्य होने चाहिए। चर्चा में सामान्य तौर यह सामने आया कि अधिकांश देशों ने जैव-विविधता के नुकसान को रोकने के लिए किसी तरह के औसत दर्जे का लक्ष्य रखने का समर्थन नहीं किया है। जिस मसौदे पर चर्चा हुई, उसके मुताबिक, 2020 के बाद की वैश्विक रूपरेखा के पहले लक्ष्य में- जैव-विविधता के क्षेत्रफल में कम से कम 15 फीसद की वृद्धि, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की कनेक्टिविटी और उसकी अखंडता, विलुप्त होने की दर को कम से कम दस गुना कम करना, प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम को आधा करना और सभी प्रजातियों के भीतर कम से कम 90 फीसदी आनुवंशिक विविधता को बनाए रखते हुए जंगली और पालतू प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता की रक्षा करना शामिल है। 2020 के बाद की वैश्विक जैव-विविधता रूपरेखा पर दो संपर्क समूह बनाए गए हैं जो संरचनात्मक प्रश्नों और पहले आठ लक्ष्यों से निपटते हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। विनोद माथुर (भारत) और नॉर्बर्ट बेयरलोचर (स्विट्जरलैंड) के सह-नेतृत्व वाले संपर्क समूह ने सम्मेलन के लक्ष्यों को तैयार करने, उन्हें व उनसे भी महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने की जिम्मेदारी निभाई। माथुर ने सम्मेलन में शामिल देशों से कहा कि वह इस पर बहस करें कि क्या जैव-विविधता को नुकसान से बचाने के लक्ष्यों में संख्यात्मक मूल्यों को शामिल किया जा सकता है अथवा इन लक्ष्यों को आकांक्षापूर्ण फॉर्मूले के तौर पर ही रखना चाहिए। बहस में शामिल कई प्रतिनिधि चाहते थे कि मील का पत्थर कहे जाने वाले लक्ष्यों से दूरी बनाई जाए, क्योंकि ये जटिलता का एक अनावश्यक स्तर जोड़ते हैं और नकल पैदा करते हैं। इन मील के पत्थरों से दूरी के बनाने के पक्ष में दूसरा तर्क यह है कि इन्हें देश के स्तर पर राष्ट्रीय-लक्ष्यों में बदलने में कठिनाई होती है। कई देशों के पास प्रगति को मापने के लिए आधारभूत आंकड़े नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि विलुप्त होने की दर को दस गुना कम करना है, तो इसकी आधारभूत दर पहले तय करनी होगी। दूसरी ओर कुछ देशों ने मील के पत्थर लक्ष्यों को शामिल करने का समर्थन किया। उनका कहना था कि 2030 के लक्ष्यों को पाने में मील के पत्थर आवश्यक पड़ाव है। वैकल्पिक रूप से, कई प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि विलुप्त होने की दर में दस गुना कमी का लक्ष्य तय करने के बजाए, 2050 तक ज्ञात प्रजातियों के मानव-प्रेरित विलुप्त होने को रोकना' लक्ष्य होना चाहिए।

आम के पौधे वायु गुणवत्ता में 20 फीसदी तक सुधार करने में सक्षम

घर के अंदर लगे पौधे जहां वातावरण को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा भी देते हैं। लेकिन क्या सच में यह हाउसप्लांट वायु प्रदूषण को कम करने में मददगार होते है, इसे समझने के लिए हाल ही में बर्मिंघम विश्वविद्यालय के नेतृत्व में एक अध्ययन किया गया है, जिसमें इस बात की वैज्ञानिक पुष्टि भी हो गई है। रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी (आरएचएस) के सहयोग से किए गए इस शोध से पता चला है कि घर और दफ्तरों के अंदर लगे आम पौधे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (एनओ-2) के स्तर में 20 फीसदी तक की कमी ला सकते हैं। उनके द्वारा किया यह अध्ययन जर्नल एयर क्वालिटी, एटमॉसफेयर एंड हेल्थ में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन आमतौर पर यूके के घरों में पाए जाने वाले तीन हाउस प्लांटस पर किया है, जिनका रखरखाव आसान है और वो अधिक महंगे भी नहीं हैं। इनमें पीस लिली, कॉर्न प्लांट और फर्न अरुम (जमीओकुलकस जमीफोलिया) शामिल थे। वैज्ञानिकों ने इन हरेक पौधे को एक टेस्ट चेम्बर में रखा था, जिसका वातावरण ठीक वैसा ही था जैसे किसी व्यस्त सड़क के किनारे स्थित कार्यालय में होता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि सभी पौधे, प्रजातियां अलग होने के बावजूद कमरे में से लगभग में मौजूद आधी एनओ-2 को दूर करने में सक्षम थे। पौधों का प्रदर्शन वातावरण पर निर्भर नहीं था। उदाहरण के लिए चाहे वो प्रकाश में रखे गए थे या अंधेरे में या फिर उनकी मिट्टी गीली या सुखी थी इस बात का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। इस बारे में शोध से जुड़े प्रमुख शोधकर्ता क्रिश्चियन फ्रांग का कहना था कि हमने जो पौधे चुने वो सभी एक दूसरे से बहुत अलग थे, फिर भी उन्होंने वातावरण से एनओ-2 को वातावरण से दूर करने में एक जैसी क्षमता का प्रदर्शन किया था। उनके अनुसार यह उनके पिछले अध्ययन से बहुत अलग था जिसके अनुसार इंडोर प्लांट किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं वो दिन रात या मिट्टी में पानी की मात्रा जैसे पयाज्वरणीय कारकों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। शोधकर्ताओं ने इस बात की भी गणना की है कि एक छोटे यानी 15 वर्ग मीटर और मध्यम आकार के कार्यालय के लिए वेंटिलेशन कितना मायने रखता है। शोध के मुताबिक छोटे कार्यालय में जहां प्रदूषण का स्तर ज्यादा है और वेंटिलेशन पर्याप्त नहीं है वहां पांच हॉउसप्लांट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर को 20 फीसदी कम कर सकते हैं। हालांकि बड़े कमरे में इसका प्रभाव केवल 3.5 फीसदी होगा, जिसमें पौधों की संख्या में इजाफा करके सुधार किया जा सकता है। हालांकि इतना तो स्पष्ट है कि यह पौधे एनओ2 के स्तर में महत्वपूर्ण रूप से कमी ला सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे करते है यह अभी भी रहस्य है।

डॉग द्वारा एक्रोबेटिक स्टंट का शानदार प्रदर्शन किया गया, शो ने दर्शकों को अपने आकर्षक करतब से मंत्रमुग्ध किया

भोजपाल महोत्सव मेले में डॉग शो में दिखाए करतब

भोपाल। संवाददाता

राजा भोज की नगरी भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर चल रहे भोजपाल महोत्सव मेले में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा डॉग शो का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि देश आजादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसके तहत सीमा सुरक्षा बल देशभर में कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसी श्रृंखला में अजय कुमार कमांडेंट व विजेंद्र सिंह उप कमांडेंट 151 बटालियन सीमा सुरक्षा बल द्वारा भोजपाल महोत्सव मेले में डॉग शो का अयोजन किया गया। डॉग शो में करीब 17 तरह के हैरत अंगेज करतब दिखाए गए। सीमा सुरक्षा बल के डॉग ट्रेनर द्वारा, राज्य के प्रशासनिक अधिकारी, केंद्र सरकार के अधिकारी और स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी में डॉग प्रशिक्षण का प्रदर्शन अद्भुत और शानदार रहा। डॉग द्वारा एक्रोबेटिक स्टंट का शानदार प्रदर्शन किया गया। इस शो ने दर्शकों को अपने आकर्षक करतब से मंत्रमुग्ध कर दिया। उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षित डॉग सीमा सुरक्षा बल के पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर भारत की रक्षा की पहली पंक्ति की अभेद्य दीवार के रूप में खड़े बॉर्डरमैन की ड्यूटी करते समय बेहद मददगार होते हैं।

टेकनपुर से आए थे सभी डॉग

सभी डॉग बीएसएफ की डॉग ट्रेनिंग स्कूल राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र (एनटीसीडी) टेकनपुर ग्वालियर द्वारा प्रशिक्षित हैं। इसमें विदेशी नश्ल के लेब्राडोर, जर्मन शेपर्ड, बेल्जियन मेलोनोइस के साथ ही देशी नश्ल के उत्तर प्रदेश का रामपुर हाउंड, कर्नाटक का मुधोल हाउंड और तमिलनाडु का राजापलम हाउंड शामिल हुए। कार्यक्रम के लिए 151 बटालियन बीएसएफ भोपाल द्वारा एनटीसीडी टेकनपुर ग्वालियर से एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया था।

पहली बार हुआ डॉग शो

मेला अध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि मेला लगाने का हमारा मुख्य उद्देश्य छोटे-छोटे दुकानदारों को रोजगार देने के साथ ही शहरवासियों का विभिन्न माध्यमों से मनोरंजन कराना है। मनोरंजन की इस श्रृंखला में मेला समिति के प्रयासों से डॉग शो का अयोजन किया गया। इस तरह का आयोजन राजधानी में संभवत: पहली बार किया गया है।

यह रहे मौजूद

इस मौके पर मेला संयोजक विकास वीरानी, महामंत्री हरीश कुमार राम के साथ ही मेला समिति के वीरेंद्र तिवारी, शुनील शाह, मधु भवनानी, चंदन वर्मा, महेंद्र नामदेव, विनय सिंह, दीपक शर्मा, दीपक बैरागी, शैलेंद्र सिंह जाट, अखिलेश नागर, केश कुमार शाह आदि मौजूद रहे।

ब्रजवाशी ने दी शानदार प्रस्तुति

प्लेबैक सिंगर हेमन्त ब्रजवासी भोजपाल महोत्सव मेला के सांस्कृतिक मंच पर अपनी प्रस्तुति दी। हेमंत अब तक कई रियल्टी शो में हिस्सा ले चुके हैं। इसमें सा रे गा मा प, इंडियन गॉट टैलेन्ट, इंडियन म्यूजिक प्रोलीक आदि शामिल है। ये राइजिंग स्टार टू के विजेता रह चुके हैं। हेमंत कई फिल्मों में अपनी आवाज दे चुके हैं। अब ये भोपाल में चल रहे भोजपाल महोत्सव मेले में धमाल मचाया।

उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने की घोषणा

प्रदेश में अब फल, फूल और सब्जियों के बीज में नहीं चलेगी ठेकेदारी प्रथा

भोपाल। संवाददाता

एमपी एग्रो के अधिकृत ठेकेदारों के माध्यम से किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत दिए जाने वाले फल, फूल और सब्जियों के बीज की व्यवस्था अब बंद होगी। किसानों को अनुदान की राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे उनके खातों में दी जाएगी। यह घोषणा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने मंगलवार को विधानसभा में की। यह व्यवस्था 2019 के पहले लागू थी। कांग्रेस विधायक हिना कांवरे ने कहा कि फल, फूल और सब्जियों के बीज, दवा, खाद और उपकरण एमपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से उपलब्ध की व्यवस्था किसानों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। विभिन्न योजनाओं में एमपी एग्रो से अधिकृत ठेकेदारों से बीज-खाद आदि चीजें ली जाती हैं,

जबकि ये बाजार में कम दर पर मिलती हैं। उद्यानिकी मंत्री ने कहा कि ठेकेदारी प्रथा कांग्रेस की सरकार में जून 2019 में लागू हुई थी। एमपी एग्रो से सामग्री लेने के लिए उसे नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया था। पूरक पोषण आहार की व्यवस्था भी ठेकेदारों के हाथ में दे दी गई थी।

अप्रैल से किसानों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ठेकेदारी प्रथा बंद करके पोषण आहार का काम महिला स्व-सहायता समूहों को दे दिया। ठेकेदारों द्वारा जिस दर पर बीज उपलब कराया जा रहा है, उससे कम दर पर बाजार में कहीं मिल रहा है तो प्रमाण उपलब्ध कराएं। हम जांच कराएंगे और अप्रैल 2022 से फल, फूल और सब्जियों पर किसानों को सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभ देंगे।

सीएम ने खरीदी गौकाष्ठ और लकड़ी बचाने का किया आह्वान

भोपाल में होलिका दहन के लिए बिका 1222 क्विंटल गौकाष्ठ

दस रुपए किलो की दर से उपलब्ध, सीएम शिवराज ने भी खरीदा गौकाष्ठ

भोपाल। शहर की हरियाली को बचाने और गौ-माता के संवर्धन के पवित्र भाव को लेकर गौकाष्ठ संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण समिति ने शहर में 31 गौकाष्ठ विक्रय केंद्र बनाए। शहर की जनता ने इस पर्यावरण हितैषी मुहिम का हिस्सा बनते हुए सभी केंद्रों से भरपूर मात्रा में गौकाष्ठ की खरीदी की। इससे पहले भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया व नगर निगम आयुक्त केवीएस चौधरी ने माता मंदिर के गोकाष्ठ केंद्रों पर आकर लोगों को गौकाष्ठ खरीदने के लिए जागरूक किया। शहर में गौकाष्ठ से ही होलिका दहन को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने गौकाष्ठ परिवार के सकारात्मक प्रयासों की सराहना की। वहीं कोलार स्थित मंदाकिनी ग्राउंड, मानस उद्यान, भोजपुर क्लब,

श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर और माता मंदिर सहित सभी केंद्रों पर 1222 क्विंटल से ज्यादा गौकाष्ठ बिका। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माता मंदिर स्थित प्लेटिनम प्लाजा के सामने होलिका दहन के लिए गौ-काष्ठ की खरीदारी की। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से लकड़ियों के स्थान पर गौकाष्ठ का उपयोग करने का आह्वान किया।

शहर में 65 प्रतिशत गौकाष्ठ से लोगों ने होली जलाई। शहर की गौशालाओं से गोकाष्ठ लाकर केंद्रों पर विक्रय की गई। इस गौकाष्ठ को शहरवासियों को उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए विक्रय केंद्र तक पहुंचने के बाद इसकी कीमत 15 रुपए प्रतिकिलो रही है। लेकिन इसे 10 रुपए प्रतिकिलो की दर पर उपलब्ध कराया गया।

मम्तेश शर्मा, समन्वयक, गौकाष्ठ समिति

कृषि विज्ञान केंद्र से किसानों को उन्नत खेती की तकनीकी जानकारी सीखने और अपनाने का आह्वान

शिवपुरी जिले में मसाला फसलोत्पादन की असीम संभावनाएं

खेमराज मौर्य। शिवपुरी

बागवानी में एकीकृत विकास मिशन अंतर्गत मसाला फसलों में तकनीकी हस्तांतरण कृषक प्रशिक्षण, सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय कालीकट केरल (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा प्रायोजित का आयोजन कृषि विज्ञान केन्द्र, शिवपुरी द्वारा गत दिवस किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रहलाद भारती, उपाध्यक्ष पाठ्य पुस्तक निगम मप्र शासन (राज्य मंत्री दर्जा) तथा विशिष्ट अतिथि यूएस तोमर, उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, एसएस कुशवाह, सहायक संचालक उद्यानिकी, जिला शिवपुरी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एसपी सिंह द्वारा की गई।

अतिथियों द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती पर माल्यार्पण कर किया। केन्द्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एसपी सिंह द्वारा कार्यक्रम की महत्ता बतलाते हुए मसाला फसलों की संभावनाओं के बारे में कार्यक्रम की उपयोगिता को बताया गया। डॉ. आईएस नरूका, नोडल ऑफिसर एमआईडीएच कार्यक्रम एवं सह संचालक अनुसंधान, रा.वि.सिं.कृ.विवि ग्वालियर ने ऑनलाइन माध्यम से भी मसाला फसलों की खेती एवं उनके लाभकारी

परिणामों के बारे में किसानों को जानकारी दी। मुख्य अतिथि प्रहलाद भारती द्वारा कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कृषि विज्ञान केन्द्र से कृषकों को उन्नत खेती की तकनीकी जानकारी सीखने और अपनाने के बारे में आह्वान किया गया।

प्रधानमंत्री द्वारा प्रोत्साहित की जा रही प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के बारे में और अधिक कृषकों को रुचि लेने के लिए कहा गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कृषकों के हितार्थ संचालित की जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं के बारे में बताया। कृषि विज्ञान केन्द्र, शिवपुरी के वैज्ञानिकों डॉ. एमके भार्गव, डॉ. शैलेन्द्र सिंह कुशवाह द्वारा मसाला फसलों अजवाइन एवं धनिया की उत्पादन तकनीक एवं जिले में संभावनाओं के बारे में तकनीकी जानकारी की गई। जेसी गुप्ता एवं डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा मसाला फसलों धनिया के कीट रोग तथा मसाला फसलों की उन्नत प्रजातियों के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण में कृषक-वैज्ञानिक परिचर्चा सह प्रश्नोत्तरी करते हुए कृषकों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विकासखंडों से आऐ कृषकों-कृषक महिलाओं 300 से अधिक को केन्द्र पर धनिया बीजोत्पादन इकाई तथा अन्य प्रदर्शन सह परीक्षण यूनिटों का भ्रमण भी गया। जिले के सफल और प्रगतिशील किसानों से परिचर्चा में अपने अनुभवों को भी साझा कराया गया।

कार्यक्रम में उपस्थित सभी किसानों को पोषण वाटिका के लिए सब्जी बीजों की बीज किट भी प्रदाय की गई। केन्द्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. एसपी सिंह द्वारा कृषकों से प्रश्नोत्तरी करते हुए सही उत्तर देने वालों को पारितोषिक रूप में कृषि एवं पशुपालन के लिए लाभकारी सामग्री भी प्रदाय की गई। कार्यक्रम का संचालन डॉ. एमके भार्गव द्वारा किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में केन्द्र के सभी वैज्ञानिकों एवं अन्य सहयोगी स्टॉफ नीरज कुमार कुशवाहा, विजय प्रताप सिंह, सतेन्द्र गुप्ता, आरती बंसल, नीतू वर्मा एवं वीरनारायण राणा का सहयोग रहा। कार्यक्रम के बाद केन्द्र की प्रदर्शन इकाइयों तथा धनिया बीजोत्पादन इकाई का अवलोकन भी कृषकों को कराया गया।

गोदाम पर गेहूं की क्वालिटी जांचने के लिए नियुक्त करें सर्वेयर

अब गोदामों पर लगाएंगे सोलर पैनल और जीपीएस

-समीक्षा बैठक में खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव ने दिए निर्देश

वंदना बृजेश परमार। उज्जैन

अनाज गोदामों पर जल्द ही सोलर पैनल और ग्लोबल पाजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) लगवाए जाएंगे। इससे बिजली खर्च घटेगा और गेहूं के भंडारण और परिवहन की 24 घंटे निगरानी की जा सकेगी। अभी इसके प्रथम चरण का परीक्षण चल रहा है। यह जानकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने हाल ही में संभागभर के कलेक्टर और कृषि, सहकारिता, नापतौल एवं एफसीआई के अधिकारियों को दी। वे बृहस्पति भवन में गेहूं की समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीदी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत कंट्रोल से मिलने वाले राशन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने गोदाम पर गेहूं की क्वालिटी जांचने को सर्वेयर नियुक्त करने के निर्देश दिए। कहा की किसी भी सूरत में वेयर हाउस

में सात दिन से ज्यादा गेहूं का भंडारण न करें। गेहूं का परिवहन करें। समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों पर कृषि विभाग एक नोडल अधिकारी तैनात करें जो गेहूं की क्वालिटी जांच रहे। पिछले वर्षों में उपार्जन समितियों पर जो शेष राशि बकाया है, उसकी वसूली करें। वसूली के समय यह ध्यान रखें कि जिस समिति से वसूली करनी है, उसी से ही राशि की वसूली की जाए। ठीक से काम करने वाली समितियों को अनावश्यक परेशान न किया जाएं। गेहूं की सफाई के लिए मशीनें लगाना सुनिश्चित करें। वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन से उपार्जन का सर्कुलर मंगाकर उसका अध्ययन करें और गोदाम में आवश्यक साफ-सफाई रखें। दवा का छिड़काव कराएं। उपार्जन केंद्रों के तौलकांटों का सत्यान करें और सीमावर्ती जिलों एवं राज्यों पर नजर रखें। अपने जिले का गेहूं पहले खरीदें। उन्होंने उपार्जन मंडी मिलान प्रणाली उज्जैन माडल की सराहना की। कहा कि रेलवे बोर्ड से बात हो गई है। जहां-जहां आवश्यकता होगी, वहां-वहां अतिरिक्त रैक पाइंट बनाए जाएंगे।

कलेक्टर ने कहा-किसानों ने होल्ड कर लिया गेहूं

कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रमुख सचिव को बताया कि किसानों ने अपना गेहूं होल्ड कर लिया है। इसलिए मंडी और समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र पर गेहूं की आवक रुक गई है। उन्होंने गेहूं गांव में ही होल्ड कर लिया है। उन्हें अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद है। वे दाम बढ़ने का इंतजाम कर रहे हैं। देवास के जिला पंचायत सीईओ प्रकाशसिंह चौहान ने बताया कि जिले में पिछले वर्ष की तुलना में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने वाले किसानों का पंजीयन इस साल 25 फीसद कम हुआ है। अब तक 34 हजार मैट्रिक टन गेहूं की ही खरीदी हुई है। प्रतिदिन चार हजार मैट्रिक टन गेहूं आ रहा है। शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन ने बताया कि इस बार चना एवं मसूर का रकबा बढ़ा है। तीन लाख मैट्रिक टन उपार्जन का अनुमान है। आगर-मालवा कलेक्टर अवधेश शर्मा ने बताया कि किसान बढ़े हुए रेट की ओर जा रहे हैं। एक लाख 25 हजार मैट्रिक टन गेहूं के उपार्जन की संभावना है। रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि 62 हजार हेक्टेयर में गेहूं बोया था। एक लाख 50 हजार मैट्रिक टन गेहूं की आवक की संभावना है। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह ने बताया कि 63 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं का रकबा है। एक लाख 75 हजार मैट्रिक टन उपार्जन का अनुमान है। नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि किसान बढ़े हुए दाम का इंतजार कर रहा है। गेहूं के अलावा चना, मसूर, सरसों का रकबा बढ़ा है।

कृषि विवि के डॉ. शेखर बघेल बोले-ड्रोन की मदद से खेती करना धीरे-धीरे होता जा रहा आसान

किसान पूछ रहे, भैया कैसे चलाते हैं ड्रोन

जबलपुर। संवाददाता

खेती में नई तकनीक का उपयोग कर किसान अब अपनी लागत कम कर मुनाफा बढ़ाने में जुट गए हैं। ज्यादातर किसान इन दिनों नई-नई तकनीकों को सीख कर उसे खेती में अपना रहे हैं। इन्हीं नई तकनीकों में से एक है ड्रोन के माध्यम से फसलों में कीटनाशक का छिड़काव करने का तरीका। कई किसान अब ड्रोन चलाने वालों से संपर्क कर उनसे इसे चलाने का तरीका सीख रहे हैं। ड्रोन उड़ाने वाले बताते हैं कि अब किसानों को अपनी फसल में कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए इन ड्रोन की जरूरत तेजी से बढ़ने लगी है। यही वजह है कि वह कभी यूट्यूब के माध्यम से तो कभी शहर में ड्रोन संचालक के माध्यम से इस तकनीक को अपने खेतों में भी अपना रहे हैं। दरअसल, इस बार केंद्रीय और राज्य के बजट में खेती में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई रियायत गई है। कृषि में ड्रोन की मदद से आज न सिर्फ फसलों में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है, बल्कि फसलों के नुकसान और सर्वे करने का काम भी इनकी ही मदद से किया जा रहा है। कृषि विज्ञानी के मुताबिक आने वाले समय में ड्रोन से खेती में बोवनी का भी काम किया जा सकेगा।

आसान हो जाएगा ड्रोन का उपयोग

ड्रोन एक्सपर्ट अभिनव ठाकुर बताते हैं कि लगातार ड्रोन को अपग्रेड किया जा रहा है। अब जब केंद्र सरकार ने खेती में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने का कदम उठाया है, तो इससे ड्रोन बनाने वाले और इसका उपयोग करने, दोनों को राहत मिलेगा। वे बताते हैं कि गूगल मेप की मदद से खेत का नक्शा चुनने के बाद यह अपने आप खेत के एरिया में स्प्रे करता है। वहीं दवा अथवा बैटरी खत्म होने की स्थिति में ड्रोन वापस अपनी जगह पर लौट आता है। ड्रोन से दवा के छिड़काव से किसानों को खेतों में नहीं जाना पड़ता, जिससे फसलों को नुकसान नहीं पहुंचता और किसान भी दवाओं से होने वाले दुष्प्रभाव से बचता है।

ड्रोन की मदद से खेती करना धीरे-धीरे आसान होता जा रहा है। जहां खेत में कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए पहले कई मजदूर लगते थे, लेकिन अब ड्रोन की मदद से यह काम चंद मिनटों में हो जाता है।

डॉ. शेखर बघेल, वरिष्ठ वैज्ञानिक, जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि

सीएम शिवराज बोले-मध्यप्रदेश गेहूं के उत्पादन में देश में प्रथम

मसाला फसलों की खेती और एक्सपोर्ट पर सरकार करेगी फोकस

-प्रदेश का बुरहानपुर जिला नगदी फसल लेने वाला जिला बना

भोपाल। संवाददाता

मध्य प्रदेश सरकार ने मसाला फसलों की खेती और उसके एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि फसलों के विविधीकरण से किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण संभव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परंपरागत फसलों के साथ अधिक लाभ वाली फसलें लेने के लिए किसानों को निरंतर प्रोत्साहित कर रहे हैं। बुरहानपुर ने मसाला फसलों के उत्पादन में विशेष स्थान बनाया है, यहां हल्दी, अदरक, धनिया, प्याज का बड़ी मात्रा में उत्पादन हो रहा है। केला, गन्ना और कपास में भी बुरहानपुर अग्रणी है। मुख्यमंत्री चौहान बुरहानपुर में मसाला फसलों के उत्पादन, प्रसंस्करण और प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को आज अपने निवास कार्यालय से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की गई है। इसमें सिंचाई सुविधाओं के विस्तार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सिंचाई का रकबा बढ़ने से उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा है। मध्यप्रदेश, गेहूं के उत्पादन में देश में प्रथम है। बुरहानपुर जिला नगदी फसल लेने वाला जिला माना जाता है। यहां फल, फूल और औषधीय पौधों की खेती को और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

मसालों के निर्यात में अपना विशेष स्थान बनाएगा एमपी

मुख्यमंत्री ने कहा कि मसालों के उत्पादन में देश का विश्व में सदियों से नाम रहा है। दुनिया के कई देश में भारत से मसाले जाते रहे हैं, इसमें दक्षिण के राज्य आगे रहे हैं। अब जिस गति से मध्य प्रदेश में मसालों की खेती हो रही है, उससे निश्चित ही बुरहानपुर सहित प्रदेश भी मसालों के निर्यात में अपना विशेष स्थान बनाएगा। इसके लिए उन्नत तकनीक का उपयोग कर उत्पादन के साथ पैकेजिंग, क्वालिटी कंट्रोल, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर ध्यान देना आवश्यक है। किसानों के साथ शासकीय एजेंसी और कृषि विशेषज्ञों को परस्पर समन्वय से कार्य करना होगा।

समय की जरूरत प्राकृतिक खेती | मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देना समय की आवश्यकता है। खेती में कीटनाशक और फर्टिलाइजर के बढ़ते उपयोग से मानव स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। पशुपालन और खेती को समन्वित कर प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा सकता है। पारंपरिक रूप से बनने वाली गोबर की खाद और गौ-मूत्र से बनने वाले कीटनाशक का उपयोग फसलों के लिए सुरक्षित हैं। मुझे विश्वास है कि मसालों की खेती के साथ प्राकृतिक खेती में भी बुरहानपुर अपना विशेष स्थान स्थापित करेगा।

कार्यशाला में ये हुए शामिल

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन में हर घर में नल से जल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 30 अप्रैल को बुरहानपुर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पानी पंचायत का आयोजन किया जाएगा। जिले के प्रत्येक गांव में जल महोत्सव भी होगा। कार्यशाला में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विवि ग्वालियर एवं जबलपुर, केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान भोपाल, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय पुणे, स्पाइस बोर्ड केरल और भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र केरल के विशेषज्ञ शामिल हुए।

औषधीय गुणों के कारण पशु आहार के सहयोगी तत्व के रूप में अपनाएं

हर्बल औषधियों के मिश्रण से बढ़ाएं पशु आहार की गुणवत्ता और आमदनी

भोपाल। संवाददाता

प्राकृतिक हर्बल उत्पादों का उपयोग अक्सर एंटी-बैक्टीरियल (बैक्टीरिया रोधी), एंटी-मायकोटिक्स (कवकता रोधी), एंटी-पैरासिटिक्स (परजीविता रोधी), कीटाणुनाशक और प्रतिरक्षा उत्तेजक के रूप में किया जाता है। हर्बल आहार एडिटिव्स के इस्तेमाल से पशुओं का आहार स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक बनता है। इससे दूध उत्पादन और उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। दुनिया का सबसे बड़ा पशुधन भारत में है। 20वीं पशुधन गणना-2019 के अनुसार, देश में पशु धन की कुल आबादी करीब 53.6 करोड़ है। ये 19वीं पशुधन गणना -2012 की तुलना में 4.6 प्रतिशत ज्यादा थी। पशुधन की बढ़ती आबादी को देखते हुए उम्दा चारा और पौष्टिक पशु आहार की मांग का भी तेजी से बढ़ना लाजमी है। इसी चुनौती को देखते हुए पशु विशेषज्ञों की ओर से पशुपालक किसानों को चारा फसलों और पौष्टिक पशु आहार के बारे में अनेक सलाह दी जाती है। ऐसी ही एक बेहद उपयोगी सलाह है-हर्बल फीड एडिटिव्स। खेती-किसानी की दुनिया का पशुधन एक अभिन्न अंग है। इसीलिए कृषि और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक असर रहता है। पशुओं के उत्पादन, उनके रोग की रोकथाम और उपचार तथा पर्यावरण के अनुकूल पशुओं का पोषण- ये सभी पहलू पशुधन विशेषज्ञों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण पशु उत्पादों को प्राप्त करने के लिए पशुओं को स्वस्थ रखना आवश्यक है। जड़ी-बूटियों, हर्बल तैयारियों और अन्य वनस्पति जैसे प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले यौगिकों का उपयोग समग्न पशु स्वास्थ्य को बढ़ाने में कारगर है।

विभिन्न हर्बल आहार एडिटिव्स, इनके सक्रिय घटक और उपयोग

पौधा	पौधे का भाग	उपयोगिता
जायफल	बीज	पाचन उत्तेजक और दस्त को रोकने वाला
दालचीनी	छाल	भूख और पाचन उत्तेजक, संक्रमण रोकने वाला
लौंग	लौंग	भूख और पाचन उत्तेजक, संक्रमण रोकने वाला
इलायची	बीज	भूख और पाचन उत्तेजक
धनिया	पत्तियां और बीज	पाचन उत्तेजक
जीरा	बीज	पाचन से बनने वाली गैस को रोकना और दूध के स्राव को बढ़ाने वाला
मोटी सौंफ	फल	पाचन उत्तेजक और दूध के स्राव को बढ़ाने वाला
अजवायन	फल और पत्तियां	भूख और पाचन उत्तेजक
अजमोद	पत्तियां	भूख और पाचन उत्तेजक, संक्रमण रोकने वाला
मेंथी	बीज	भूख उत्तेजक
मिर्च	फल	पाचन उत्तेजक
हॉसरैडिश	जड़	भूख उत्तेजक
सरसों	बीज	पाचन उत्तेजक
अदरक	कन्द	गैस्ट्रिक उत्तेजक
लहसुन	कन्द	पाचन उत्तेजक और संक्रमण रोकने वाला
दौनी	पत्तियां	पाचन उत्तेजक और संक्रमण रोकने वाला
अजवायन	पूरा पौधा	पाचन उत्तेजक, ऑक्सीकरणरोधी और संक्रमण रोकने वाला
पुदीना	पत्तियां	भूख और पाचन उत्तेजक, संक्रमण रोकने वाला
शतावरी	जड़	गैस्ट्रिक अल्सर की रोकथाम और इलाज और दूध स्राव को बढ़ाने वाला
जीवन्ति	पत्तियां और टहनिया	दूध के स्राव को बढ़ाने वाली, रोगाणुरोधी और सूजन को रोकने वाली

सहयोगी पशु आहार है हर्बल फीड एडिटिव्स

पशुपालक किसान अच्छी तरह जानते हैं कि इंसान की तरह ही पशुओं के आहार का भी पौष्टिक और सन्तुलित होना बेहद जरूरी है। जिस तरह अनेक जड़ी-बूटी, फल-फूल और मसाला बगैरह इंसान की सेहत के लिए बहुत उपयोगी हैं। वैसी ही खूबियां पशुओं के लिए भी उपयोगी हैं। हर्बल आहार एडिटिव्स के इस्तेमाल से पशुओं का आहार स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक बनता है। इससे दूध उत्पादन और उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। इनका इस्तेमाल दवा, हर्बल अर्क या हर्बल आइसोलेट में किया जा सकता है। स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान, जयपुर के विशेषज्ञों के अनुसार, हर्बल उत्पाद किसी पौधे, शैवाल, फफूंद या कवक या लाइकेन का एक पूरा या कटा हुआ तथा सूखा हिस्सा होता है। इसके औषधीय गुणों के कारण इसे पशु आहार के सहयोगी तत्व के रूप में अपनाया जाता है। प्राकृतिक हर्बल उत्पादों का उपयोग अक्सर एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-मायकोटिक्स, एंटी-पैरासिटिक्स, कीटाणुनाशक और प्रतिरक्षा उत्तेजक के रूप में किया जाता है।

हर्बल आहार एडिटिव्स से फायदा

पशुओं के चारे के साथ हर्बल आहार एडिटिव्स के इस्तेमाल से अनेक फायदा होता है। इससे पशुओं के पाचन में सुधार होता है। उनके चारे और आहार का प्रभावी उपापचय को सुनिश्चित करता है। पशुओं की सेहत और उनके ऊर्जा स्तर में शानदार सुधार होता है। पशुओं की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उनकी आंतों में पलने वाले परजीवी कीट-कृमि का सफाया होता है। इस तरह, हर्बल फीड एडिटिव्स ऐसे पशु आहार हैं जिनके इस्तेमाल से पशुपालकों का पशुधन ज्यादा स्वस्थ और उपयोगी बनता है तथा इसकी उत्पादकता बढ़ती है और अन्ततः किसानों की कमाई बढ़ती है।

अब उद्योग की तर्ज पर विकसित हो रही खेती की व्यवस्था

भोपाल। संवाददाता

किसानों की आय दोगुनी करने की कवायद के तहत केंद्र सरकार की कोशिश है कि पारंपरिक खेती की व्यवस्था को इंडस्ट्री की तर्ज पर विकसित किया जाए। इसके लिए खेतों में फसल उत्पादन, फिर बाजार और अंत में उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में शामिल सभी पक्षों को एकसाथ जोड़ा जा रहा है। बिचौलिया व्यवस्था के बजाय पोर्टल और ऐप आधारित व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। ऐसा ही प्रयास है किसान सभा और सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम्स फॉर फार्मर्स। इसे अब मध्यप्रदेश में भी लागू करने की कवायद जारी है। इसके तहत चेन में शामिल सभी पक्षों को ऐप आधारित सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे उनका काम आसान होगा।

किसानों के कार्ड होंगे सक्रिय

योजना को प्रदेश में लागू करने की कवायद शुरू हो गई है। अगले चरण में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किसान सभा पोर्टल के माध्यम से जोड़कर ऐप से सुविधाएं दी जाएंगी। ऐप से संपूर्ण चेन में शामिल वर्गों को जोड़ने किसान कार्ड, मंडी डीलर कार्ड, सर्विस प्रोवाइडर कार्ड और ट्रांसपोर्टर कार्ड बनाने जाएंगे। पोर्टल का लाभ लेने किसान कार्ड को सक्रिय करना जरूरी है। प्रदेश में जिस भी फर्म को काम दिया जाएगा, उसे घर घर जाकर किसानों की जानकारी अपलोड कर कार्ड को सक्रिय करना होगा।

किसान विज्ञान केंद्र नेटवर्क को भी जोड़ेंगे

किसान सभा नामक ऐप किसानों को सप्लाई चेन और ट्रांपोर्ट सुविधा से जोड़ने में मददगार है। इससे फसल, खाद और बीज की खरीदी-बिक्री का काम आसान हो गया है। इसे खासतौर पर किसान, ट्रांसपोर्टर, कृषि उद्योग से जुड़े व्यवसायियों की समस्याओं के समाधान के लिए विकसित किया गया है। यह पोर्टल किसानों, ट्रांसपोर्टर, खेती-किसानी से जुड़ी सुविधाएं देने वाले विक्रेताओं, कोल्ड स्टोरेज, मंडी डीलर और ग्राहकों को जोड़ने का काम करेगा। ऐसे में किसानों को अपने उत्पाद के लिए बाजार मुहैया कराना आसान होगा। भविष्य में इस ऐप को कृषि विज्ञान केंद्रों से भी जोड़ दिया जाएगा, ताकि किसानों को केवीके नेटवर्क का भी पूरा फायदा मिल सके।

जहां पर होती है सबसे अधिक खेती, किसानों की बढ़ रही आय

मप्र सोयाबीन और लहसुन और दलहनी फसल के लिए प्रसिद्ध

भारत के टॉप दस कृषि राज्य में अपना मध्यप्रदेश

भोपाल। संवाददाता

भारत में लगभग 60-65 फीसदी आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है और उसी से अपने जीवन का यापन करते हैं। इसके अलावा देश उच्च गुणवत्ता वाले खाद्यान्न और अन्य खाद्य वस्तुओं का भी उत्पादन करता आ रहा है। भारतीय कृषि व्यवसाय तीव्र गति से बढ़ रहा है और वैश्विक व्यापार में भी अपना भरपूर योगदान जारी रखा हुआ है। भारत का किराना और खाद्य बाजार दुनिया का छठा सबसे बड़ा बाजार है, जो कुल बिक्री का 70 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, अगले 20 वर्षों में, भारत के प्रति व्यक्ति की जीडीपी में 20 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।

जैसे-जैसे समय बीत रहा है, प्रवृत्ति भी बदल रही है। भारतीय उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं और पौधों पर आधारित प्रोटीन से हटकर पशु-आधारित प्रोटीन की ओर जा रहा है। किसान अपनी आय बढ़ाने और उपभोक्ता के आवश्यकताओं को तेजी से पूरा करने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए हमने भारत के शीर्ष दस कृषि राज्यों की एक सूची तैयार की है। जिसमें अपना मप्र भी शामिल है।

पश्चिम बंगाल| पश्चिम बंगाल भारतीय खाद्यान्न का प्रमुख उत्पादक है। वहीं आंध्र प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश अपने चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल चावल के अलावा जूट, तिल, तंबाकू और चाय उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। 2600 किलो प्रति हेक्टेयर उपज के साथ पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन कुल 146.05 लाख टन है। यह भारत के चावल उत्पादक राज्यों में से एक है।

उत्तर प्रदेश| उत्तर प्रदेश भारत का शीर्ष कृषि राज्य है। जिसमें बाजरा, चावल, गन्ना, खाद्यान्न, और कई अन्य राज्य स्तरीय फसलों का उत्पादन होता है। यह हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश से आगे है। वहीं भारत के गेहूं उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। प्रदेश में 22.5 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। वहीं गेहूं उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का मौसम अनुकूल है। प्रदेश में लगभग 96 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की खेती कि जाती है।

पंजाब| पंजाब दुनियां का सबसे उपजाऊ राज्य है। पंजाब गेहूं, गन्ना, चावल, फल और सब्जियां उगाने के लिए उत्तम स्थान माना जाता है। पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। खाद्यान्न उत्पादन कुल उत्पादक भूमि का 93 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पंजाब में है।

गुजरात| गुजरात भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है। इस राज्य ने एक विवेकपूर्ण विकास रणनीति का अनुसरण किया। उन्होंने कृषि, ऊर्जा और विनिर्माण में निवेश किया, और परिणामस्वरूप दो अंकों की वृद्धि देखी। गुजरात का मौसम अप्रत्याशित है, जिससे वहां फसल उगाना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण से यहां के किसान नई तकनीक का उपयोग कर फसलों का उत्पादन करते हैं। कपास, मूंगफली, अरंडी, बाजरा, अरहर, हरा चना, तिल, धान, मक्का और गन्ना सभी गुजरात में उगाए जाते थे। गुजरात सबसे अधिक कपास का उत्पादन करने वाला राज्य है। इसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना का स्थान आता है।

हरियाणा| हरियाणा अगला कृषि प्रधान राज्य है। हरियाणा सबसे महत्वपूर्ण कृषि योगदानकर्ताओं में से एक है। लगभग 70 फीसदी निवासी कृषि कार्य करते हैं। हरियाणा भारत की हरित क्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन सबके परिणामस्वरूप हरियाणा में एक विशाल सिंचाई प्रणाली भी है।

मध्य प्रदेश| मध्य प्रदेश अपने दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। यह सोयाबीन और लहसुन उगाने के लिए भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश दलहनी फसल उगाने के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में किसानों की आय का मुख्य स्रोत गेहूं और मक्का है। इस राज्य में उगने वाले उड़द, सोयाबीन और अरहर अन्य दालों के उदाहरण हैं।

असम| असम कृषि कार्य पर बहुत हद तक निर्भर है। असम अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम विकसित राज्यों में से एक है। असम की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह से कृषि पर केंद्रित है और कृषि 70 प्रतिशत आबादी के लिए जीविका प्रदान करती है। पानी के बाद पूरी दुनिया में चाय का सेवन नियमित रूप से किया जाता है। असम चाय उत्पादक के सबसे आगे है।

आंध्र प्रदेश| आंध्र प्रदेश में 62 फीसदी आबादी कृषि को रोजगार देती है। चावल उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश भारत के 77 प्रतिशत फसल उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, तंबाकू, फलियां, गन्ना और अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं।

कर्नाटक| कर्नाटक में कृषि कार्य पूरी अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कृषि, राज्य के अधिकांश निवासियों को रोजगार देता है। कर्नाटक की मौसम जलवायु कृषि के लिए आदर्श है. चावल, मक्का, मूंग दाल, लाल मिर्च, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, हल्दी और कपास कर्नाटक की खरीफ फसलें हैं। सरसों, तिल, जौ, गेहूं और मटर कर्नाटक की रबी फसलें हैं। कर्नाटक भारत के शीर्ष कृषि राज्यों में से एक है।

छत्तीसगढ़| छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल, बाजरा और मक्का छत्तीसगढ़ में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है। छत्तीसगढ़ में चावल की खेती 77 प्रतिशत भूमि पर की जाती है। छत्तीसगढ़ पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर है। कुल क्षेत्रफल का केवल 20 प्रतिशत सिंचित है।

गोबर खरीद के लिए अब सभी राज्यों की जिम्मेदारियां तय

भोपाल। संवाददाता

किसानों व पशुपालकों के लिए जानवरों के अपशिष्टम (गोबर) को आर्थिक तौर पर लाभकारी बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। जिसके तहत कई राज्यों में सरकार की तरफ से गाय के गोबर की खरीद की जा रही है, लेकिन कई राज्यों में अभी भी गोबर खरीद की व्यवस्था नहीं बन पाई है। इस मामले में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परुषोत्तम रूपाला ने स्पष्ट किया है कि किसानों से गाय के गोबर की खरीद की जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य इस संबंध में योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं। उन्होंने यह जानकारी बीते दिनों लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में दी है।

जैविक खाद को मिलेगा बढ़ावा

वहीं सरकार 'गोवर्धन' के जरिए खेती के कचरे से जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने की भी तैयारी कर रही है। इस संबंध की जानकारी भी बीते दिनों केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परुषोत्तम रूपाला ने लोकसभा में साझा की है। उनकी तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के प्रयासों की मदद के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय पशु गोबर और कृषि अपशिष्ट का उपयोग करके जैविक उर्वरक और ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन परियोजना नामक एक बहु-एजेंसी फ्लैगशिप कार्यक्रम लागू कर रही है, जो जल्द ही लागू की जाएगी।

डेयरी संयंत्रों में गोबर का हो रहा प्रयोग

केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में जानकारी साझा करते हुए बताया कि गोबर की क्षमता के दोहन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने आणंद जिले के मुजकुवा और जकारियापुरा गांव में खाद श्रृंखला पर सफल पायलट मॉडल स्थापित किया है। वहीं एनडीडीबी वाराणसी दुग्ध संघ में बड़े पैमाने पर अनूठे मॉडल पर भी काम कर रहा है, जिसमें गोबर आधारित बायोगैस संयंत्रों द्वारा डेयरी संयंत्रों की विद्युत और तापीय ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, बनासकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ भी सहकारी डेयरियों / उद्यमियों द्वारा गाय के गोबर और कृषि-अपशिष्ट का उपयोग करके पशु गोबर बायोगैस संयंत्र को बढ़ावा दे रहा है।

किसानों को तीन साल के लिए मिलती है वित्तीय मदद

प्राकृतिक खेती के लिए 31 हजार हेक्टेयर दे रही सरकार

भोपाल। संवाददाता

केंद्र सरकार देशभर के सभी राज्यों में गैर-रासायनिक यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। जिसके तहत सरकार दो योजनाओं के जरिए गंगा नदी के किनारे प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। केंद्र सरकार की इन योजनाओं के तहत केंद्र सरकार किसानों को बीज, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक, जैविक खाद, कम्पोस्ट वर्मी-कम्पोस्ट, वानस्पतिक अर्क आदि के लिए 31 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है, जो किसानों को तीन वर्ष के लिए उपलब्ध कराई जाती है। इन योजनाओं के अनुरूप सरकार नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कुल 120.49 करोड़ रुपए का फंड अभी तक किसानों के लिए जारी कर चुकी है। यह जानकारी केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी है।

प्राकृतिक खेती पर फोकस

केंद्र सरकार गंगा नदी के किनारे परम्परागत कृषि विकास योजना और भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के माध्यम से जैविक और प्राकृतिक खेती के नाम से गैर-रासायनिक खेती को बढ़ावा दे रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने बताया कि इन योजनाओं के तहत एक तरफ जहां 31 हजार रुपए की वित्तीय मदद किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन, प्रशिक्षण, प्रमाणन, मूल्यवर्धन और उनके जैविक उत्पादों के विपणन के लिए भी अतिरिक्त मदद प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कुल 120.49 करोड़ का फंड (आरकेवीवाई से 67.36 करोड़ और पीकेवीवाई से 34.20 करोड़) जारी किया जा चुका है।

रासायनिक खाद से बिगड़ी मिट्टी की सेहत

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने लोकसभा में लिखित प्रश्न के जवाब में कहा है कि रासायनिक उर्वरकों के संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग से मृदा स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही उन्होंने जोड़ा है कि अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत दीर्घकालिक उर्वरक प्रयोगों पर पांच दशकों से अधिक समय से की गई जांच ने संकेत दिया है कि अकेले नाइट्रोजन उर्वरक के निरंतर या अधिक उपयोग से मिट्टी के स्वास्थ्य और फसल उत्पादकता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

किसानों के दे रहे प्रशिक्षण

कृषि मंत्री ने जवाब में कहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मृदा स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए पौधों के पोषक तत्वों के अकार्बनिक और जैविक दोनों स्रोतों के संयुक्त उपयोग के माध्यम से मिट्टी परीक्षण आधारित संतुलित प्रबंधन की सिफारिश कर रही है। इसके अलावा, फलीदार फसलों को उगाने और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों के उपयोग की भी वकालत की गई है। इन सभी पहलुओं पर किसानों को शिक्षित करने के लिए आईसीएआर प्रशिक्षण प्रदान करता है।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, ज़ोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)